

यह धारा 30 का प्रावधान हो जाने के बाद वकील को इस बात का अधिकार मिलना चाहिये था कि जहां भी, जिस भी अधिकरण या न्यायालय में जहां साक्ष्य का रिकार्ड होता हो, वहां उपस्थित हो कर पैरवी कर सके। परन्तु इस प्रकार की अनेक जगहों पर वकीलों को रोका गया। यह मामला सब से पहले 1985 में लिंगप्पा पोचाना के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एआईआर 1985, सुप्रीम कोर्ट, पेज 389, 14.12.84 को निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 30 में जो वकील को अधिकार दिये गये हैं उसके बारे में एडवोकेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत अभी तक अधिसूचना अधिसूचित नहीं हुई है, इसलिए वकील को किसी अधिकरण में जहां प्रतिबंध लगा दिया गया हो वहां उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद में फिर यह मामला 1977 में पंजाब उच्च न्यायालय की फुल बैंच के अन्दर गया। वहां पर भी इसी प्रकार की अवधारणा, इसी प्रकार का विनिश्चय किया गया। यह मामला आगे और बढ़ता गया परन्तु इसके अन्दर अनेक प्रकार के ज्ञापन भारत सरकार को दिये गये, अनेक प्रकार की अदालती कार्यवाही एक के बाद एक इसके अन्दर की गई। इस प्रकार का तेजपाल सिंह के मामले में और के.टी. आडवाणी के मामले में भी निर्णय हुआ। बार कौंसिल एक्ट की धारा 14 में पूरा प्रावधान है कि वकील उपस्थित हो सकता है। परन्तु धारा 30 में जो एडवोकेट्स एक्ट में प्रावधान किया गया इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। यह अधिसूचना जारी न होने के कारण सारे देश भर के वकील आन्दोलित हो रहे हैं। अदालतों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुकदमों की पैरवी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। संविधान में साफ लिखा है। संविधान के आर्टिकल 22 में हर आदमी को इस प्रकार का अधिकार है कि अपनी इच्छा के वकील का सहयोग ले कर पैरवी करा सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एडवोकेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत, धारा 30 में जो अधिकार दिया गया है, भारत सरकार अधिसूचना अधिसूचित कर दे और अधिसूचित करने के बाद में वकीलों को इस बात का अधिकार मिल जाएगा कि वह इस धारा 30 में वर्णित जो कोर्ट हैं, अधिकरण हैं, 'any person who is authorised to take evidence or any authority'

उसके सामने उपस्थित हो सकेंगे। मैं मान कर चलता हूं कि इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी हो जाएगी तथा लाखों वकील जो देश भर में आन्दोलनरत हैं, उससे उनको राहत मिलेगी और वकीलों को ठीक प्रकार से न्याय देने में, न्यायालयों को ठीक प्रकार से विनिश्चय करने में सहयोग

मिलेगा। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, the Advocates Act was enacted in 1961. Section 30 gives the power to an advocate to practise in all forums. But nowadays, advocates are prevented from appearing before certain forums and there is a specific bar in certain Acts like the Family Courts Act and the Cooperative Tribunals Act. In several tribunals, advocates are barred to practise or to assist the court. The provisions of section 30 of the Advocates Act, 1961 has not been notified. Since it is not notified, these restrictions are coming in the way of advocates practising. The number of advocates is increasing like anything. But if they are prevented from practising before the Tribunals, they will be left with very few avenues to practise in this profession. One misconception is that if the advocates are permitted, they will drag the proceedings and they can complicate the issues. That is not correct. Instead, they can assist the court in coming to a correct conclusion. As a matter of fact, the advocates throughout India are observing a protest day to solve this problem. As Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu, I am taking care of 32,000 lawyers in Tamil Nadu and Pondicherry. I request the Central Government to notify section 30 of the Advocates Act, 1961. Thank you.

Impact of Bhopal Gas Tragedy on Future Generations, Particularly on Women

श्रीमती बीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं 14 वर्ष पूर्व विश्व की एक भयानक घटना जो हिन्दुस्तान में 2 दिसम्बर, 1984 की रात को घटी उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

भोपाल, मध्य प्रदेश में यूनियन कारबाईड फैक्ट्री जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी उससे 40 टन मिथाइल आइसो, हाइड्रोजन साइनाइड व अन्य जहरीली गैस बाहर निकली और उस भयानक रात में 8 हजार लोग पीरन मर गए। 16 हजार अब 14 वर्षों के दौरान और और भी मृत्युएं हुई हैं। लोग आज भी बिना परिवार के बिना किसी सहायता के अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर रहे हैं। पुनर्वास की व्यवस्था भी हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। हजारों लोग आज भी इलाज के लिए तरस रहे हैं हजारों लोग बीमार हैं। 14 वर्ष बाद धीरे-धीरे अब तक उसके प्रभाव निकलकर आ रहे

हैं। इन गैसों का सीधा लम्स पर प्रभाव पड़ा। दिमाग पर, किडनी पर) मसल्स पर, प्रजनन क्रियाओं पर असर पड़ा तथा टी.बी. जैसे रोग ज्यादा बढ़ने लगे हैं। आंखों के कॉटेक्ट ज्यादा बढ़ने लगे हैं जिन पर जहरीली गैस का असर हुआ। महिलाओं के एवार्शंस रेट ज्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि नेशनल जो परसेंटेज है उससे तीन गुना बढ़ गए हैं। मृत्यु दर तीन गुना बढ़ गयी है। पैरीनेटल मारटेल्सिटी दुगुनी बढ़ गयी है और निथोनेटल मारटेल्सिटी डेढ़ गुना बढ़ गयी है। उस समय की जो प्रगनेट वीमेन थीं उनके बच्चों में ग्रास मोटर एण्ड लैंग्वेज सेक्टर डेवलपमेंट में गड़बड़ हुई है। आज भी डब्ल्यू.एच.ओ. की जो रिपोर्टें हैं वह कहती हैं कि इसका असर तीन पीढ़ियों तक रहने वाला है—जो महिलाएं उस समय प्रगनेट थीं। उनके बच्चों में कन्जेनीटल गड़बड़ी का असर तीन पीढ़ियों तक रहने की संभावना है। मैं सदन के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पूरे इम्यून सिस्टम पर इस गैस का जो असर हुआ है वह हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को नष्ट करेगा या स्वस्थ समाज को जन्म नहीं देगा। इसको सुधारा जाना चाहिए। गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार भी और आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट के अनुसार भी जो अभी 2 दिसम्बर को ही अखबारों में, टाइम्स आफ इंडिया में प्रसारित हुई, उसके अनुसार भी यह निकलकर आया है कि इन रोगों के इलाज के लिए हमारे मध्य प्रदेश के जो अस्पताल हैं वे कंपीटेंट नहीं हैं। खास तौर से इस गैस ट्रेजेडी का असर महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ा है। उसके असर के चलते जो बायोलॉजिकल असर हुआ है वह तो है ही लेकिन परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं। सड़कों पर आ गए हैं, ब्रेड विनर्स नहीं रहे हैं। री-प्रोडक्टिव फंक्शन की कंपेबिलिटी... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मैडम, एक मिनट।

तो वह कम हुई है, हसबैंड से दूरियां बढ़ी हैं। 6 लाख लोग अब भी न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सदन का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहती हूँ कि आज भी हम उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अब तक जो इलाज हुए हैं वे सिंटेमैटिक इलाज हुए हैं। खांसी हुई तो दवा दे दी, बुखार आया तो थोड़ी सी दवा दे दी या बुखार आने लगा तो लंग्ज के लिए थोड़ा इलाज कर दिया। लेकिन एम.आई.सी. गैस कंपोनेंट के अनुसार जो रिसर्च हुई यह अभी बाकी है। उसके अनुसार अभी हम उनका इलाज नहीं करवा पाए हैं। वे सुविधाएं हम हॉस्पिटल में नहीं दिला पाए हैं। भोपाल में उनके इलाज के लिए जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वह भी कंपीटेंट नहीं है, कमला नेहरू हॉस्पिटल है, जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल है, लेकिन

उनमें बहुत सी मशीनें हैं जो कि अभी अनयूज्ड पड़ी हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्लीज कन्कलूड, वीणा जी।

श्रीमती वीणा वर्मा: यस, मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर 1979 में दिया था। उसके अनुसार यूनिफन कारबाइड कार्पोरेशन के अमरीका के 470 मिलियन डॉलर जो अभी मुआवज़ा देने के लिए बचे पड़े हैं और कोई सैटलमेंट नहीं हो पाया है। मेरी मांग यह है कि उसका जल्दी ही एक ट्रस्ट बनावा कर उसको डिस्बर्स किया जाए। अभी वन सिक्स्थ लैगों को ही उसका मुआवज़ा मिल पाया है और 16-17 हजार या 20 हजार के करीब इससे प्रभावित लोग हैं जो कि ईलाज के लिए तरस रहे हैं और दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): वीणा जी, प्लीज, कन्कलूड।

श्रीमती वीणा वर्मा: अंत में सिर्फ एक मांग कहना चाहूंगी, महिलाओं की तरफ से जो सब से ज्यादा असर महिलाओं पर हुआ है तो उनके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और गैस कंपोनेंट्स के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उनके रीप्रोडक्टिव ऑर्गेनिस्म पर असर हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह बात आपने पहले कही है। उसी का आप मत रिपीट करिए। कुछ अगर नई बात हो तो बताइये।

श्रीमती वीणा वर्मा: अंत में बस यही कहूंगी कि हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को सुधारने के लिए सरकार को चिंता करती ही चाहिए और केन्द्र सरकार को एक आदेश दे कर स्टेट गवर्नमेंट से वह जल्दी केन्द्र और राज्य दोनों मिल कर वह तो अनसैटलड मैटर्स हैं और जो पैसा डिस्बर्स होना है उसका ट्रस्ट बना कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): मैडम, एक मिनट। मैडम, आज ही हमारे मंत्रालय की तरफ से भोपाल दिन का आयोजन किया गया। ढाई सौ बच्चों ने वहां पेंटिंग कंपीटिशन करके उनके मन में उसके प्रति क्या भावना है, उसको उन्होंने उसमें प्रतिबिंबित किया था। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो बात आपने कही उसी बात की ओर आज ही यहां इस सदन में आने के पहले उसी समारोह के आयोजन में मैं सम्मिलित हुआ था और वहां से मैं आ रहा हूँ। इसलिए आपने जो भी बात कही है उसके ऊपर हमारा ध्यान है और उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। आज ही के दिन, इसी तरह हम हर

साल, इस दिन का आयोजन करेंगे।

श्रीमती चीणा वर्मा: धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): थैंक यू। श्री राम नाथ कोविन्द।

Indefinite Hunger Strike By SC/ST Railway Employees in Delhi Seeking Justice and Implementation of Railway Board's Directions in respect of their Demands

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं संक्षेप में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यद्यपि जिस संबंध में मैं बात कहने जा रहा हूँ वह रेल मंत्रालय से संबंधित है। यहां पर आल इंडिया एस०सी० एस०टी० रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी और सदस्य पिछले 23-11-98 से डीआरएम नई दिल्ली कार्यालय पर अपनी कुछ मांगों को ले करके भूख हड़ताल पर बैठे हैं। महोदया, मैं आज ही अभी सायं चार बजे माननीय रेल मंत्री जी से मिल चुका और यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जो टिप्पणी की थी और यह कहा कि रेल कर्मचारी यदि अपनी न्यायोचित मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं तो यह बात रेल प्रशासन के लिए अच्छी नहीं है। मैं उनसे पुनः विनती करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ और उसी समय जिस समय मैं मिला उन्होंने तुरंत उचित आदेश भी दिए कि डीआरएम स्तर पर कुछ लोग उनसे मिलें, बात करें और इस हड़ताल को तुरंत समाप्त करवाने की व्यवस्था करें।

मैं पुनः रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और विनती करता हूँ कि इस कार्य में उचित कदम तुरंत उठाएँ। धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

Re: Derailment of 8029 down Kurla-Howrah Express in Manmad-Jalgaon Section on Bhusaval Division of Central Railway on 3.12.1998.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Madam, as already informed yesterday by

Shri Nitish Kumar, Hon'ble Minister for Railways, I visited the site of accident near Jalgaon, along with Member Engineering and Member Electrical Railway Board. We also visited the civil hospital at Jalgaon.

As a result of the above accident, 9 persons (including 3 Railway staff) have lost their lives, 11 suffered grievous injuries and 23 passengers suffered simple injuries. Injured persons have been admitted in Civil Hospital, Jalgaon and utmost care is being taken to render the best possible medical treatment. However, few of the injured passengers on their own request sought discharge from the hospital.

Ex-gratia payments was announced as follows, Rs. 25,000/- for dead, Rs. 5,000/- for grievously injured and Rs. 500/- for simple injuries. Directions have also been given to railway officials to help injured passengers in filling up claims forms so that they could get the compensation from Railway Claims Tribunal expeditiously. In this accident the district administration i.e. police personnel and doctors of civil hospital, besides some voluntary organisations rendered prompt help to injured persons.

Traffic on the Down line has since been restored at 8.35 hrs. today. Commissioner Railway Safety (CRS), Central Circle, has already started the inquiry and has been asked to complete the same expeditiously. As already informed yesterday, *prima facie*, the cause of the accident appeared to be weld failure. However, on receipt of inquiry report from CRS, regarding the cause of the accident, prompt action would be taken against the persons responsible as well as remedial steps to prevent recurrence of such accidents.

On behalf of railways and myself, I express deep condolences to the bereaved families and also express sincere sympathies to the injured. I trust the House will join me in extending heartfelt condolences to the bereaved families.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, there is no point in seeking clarifications now. If the Minister agrees, it can be postponed to Monday. This is an issue of great concern. Time and again this is happening. Every time we have been discussing that safety should be given the first priority.